प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में भाग लेने की वजह से चर्चा में हैं, असल में चुनावतंत्र से धोखाधड़ी के जनक हैं

देवप्रिय अवस्थी

संघ के कार्यक्रम में जाकर वे जो गलती कर आए हैं उस बारे में उनकी बेटी शर्मिष्ठा ने उन्हें अच्छी खासी नसीहत दे ही दी है, लेकिन प्रणब दा से जुड़ा एक तथ्य उनके प्रशंसक और विरोधी दोनों ही जाने अनजाने में भूल जाते हैं। वह तथ्य है प्रणब दा द्वारा देश के संविधान और चुनाव कानूनों को ठेंगा दिखाए जाने का।

इसके लिए हमें देश के चुनावी इतिहास के कुछ पन्ने पलटने होंगे। यह बात 1981 की है। तब पश्चिम बंगाल विधानसभा में कांग्रेस की हालत बहुत पतली थी। वह वहां से राज्यसभा के लिए अपना उम्मीदवार चुनवा पाने की स्थिति में नहीं थी। इंदिरा गांधी प्रणब दा को किसी भी स्थिति में राज्यसभा में लाना चाहती थीं।

तब इंदिरा गांधी के सलाहकारों ने प्रणब दा के लिए चोर दरवाजा खोला। झूठा हलफनामा देकर प्रणब दा का नाम गुजरात की मतदाता सूची में दर्ज कराया गया और उन्हें वहां से राज्यसभा का सदस्य चुना गया। इस तरह प्रणब दा ने एक पूरे कार्यकाल तक राज्यसभा में गुजरात का प्रतिनिधित्व किया। इस नाते वे गुजरात से अपने खास संबंधों की बात भी कई बार दोहरा चुके हैं।

सवाल है कि क्या गुजरात की मतदाता सूची में प्रणब दा का नाम दर्ज कराने की पूरी प्रक्रिया तत्कालीन चुनाव कानून-नियमों के तहत सही थी। क्या चुनाव आयोग ने प्रणब दा की इस चुनावी जालसाजी की जानबूझकर अनदेखी नहीं की थी? क्या तत्कालीन विपक्ष ने इस मुद्दे को इसलिए गंभीरता से नहीं लिया था कि उसे अपने लिए भी यह चोर दरवाजा मुफीद लगता था? संविधान निर्माताओं ने राज्यसभा को राज्यों के सदन की भी संग्या दी थी। क्या प्रणब दा का यह कृत्य संविधान निर्माताओं की भावनाओं का मखौल उड़ाना नहीं था?

प्रणब दा ने 1981 में राज्यसभा में पहुंचने के लिए जिस चोर दरवाजे का इस्तेमाल किया, बाद में उस चोर दरवाजे का इस्तेमाल कम से कम दो प्रधानमंत्रियों, दर्जनों मंत्रियों और 50 से ज्यादा सांसदों ने भी किया। मनमोहन सिंह और इंद्रकुमार गुजराल के नाम असम और बिहार की मतदाता सूची में झूठे हलफनामों के आधार पर ही जोड़े गए।

लंबे समय तक पीएम इन वेटिंग रहे लालकृष्ण आडवाणी का नाम भी इसी रास्ते से गुजरात की मतदाता सूची में जुड़ा। आज भी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, वित्त मंत्री अरुण जेटली और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के नाम जिन राज्यों की मतदाता सूची में शामिल हैं वहां व्यावहारिक तौर पर वे कभी रहे ही नहीं। माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने भी राज्यसभा आने के लिए अपना नाम बंगाल की मतदाता सूची में दर्ज कराया था। और तो और, ईमानदारी के सबसे बड़े स्वंयभू ठेकेदारों में एक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम भी दिल्ली की मतदाता सूची में उस पते पर दर्ज है जहां वह कभी रहे ही नहीं।

मतदाता सूची किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार होती है , लेकिन सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने आपसी मिलीभगत से उसका मखौल बना रखा है। चुनाव आयोग ने भी जानबूझकर आंखें मूंद रखी है। ऐसे लोकतंत्र को गिरोह तंत्र या ढोंग तंत्र न कहें तो क्या कहें।

'राष्ट्रवाद' का असली बदरंग घिनौना चेहरा - देशी-विदेशी हथियार सौदागरों के पौ बारह और आम सैनिकों के लिए खाना, वर्दी, जूते भी नदारद!

मुकेश असीम

इकनॉमिक टाइम्स की खबर है कि लड़ाकू हथियार खरीदने के लिए होने वाले भारी खर्च के चलते सरकार ने ओर्डनेंस कारखानों से होने वाली ख़रीदारी को उनके कुल उत्पादन के 94% से घटाकर 50% कर दिया है। यही कारखाने सैनिकों के लिए जरूरी अधिकांश साजो-सामान - वर्दी, जूते, बेल्ट, टोपी, आदि मुहैया कराते हैं। हालत यहाँ तक आ पहुंची है कि अब सैनिकों को इन सामानों की ख़रीदारी खुद बाजार से करना मजबूरी बन जाने वाली है।

इसके पहले ही फौज से लेकर अर्धसैनिक बलों के जवानों की खराब भोजन की बहुतेरी शिकायतें, वीडियो सहित, सामने आईं थीं जिन्हें बाद में फौज ने सख्त पाबंदी और सजाओं द्वारा दबा दिया था। हमेशा सेना के सम्मान की बातें बघारने वाले भक्तों ने इन जवानों के खिलाफ भी गालियों का मोर्चा खोल दिया था। पर अब सच्चाई सामने है कि हथियार बेचने वाले देशी-विदेशी पूँजीपतियों से ऊंची कीमतों पर की जा रही भारी ख़रीदारी और बड़े अफसरों के ऐशो आराम पर बड़े खर्च के चलते आम जवानों की जिंदगी लगातार मुश्किल होती जा रही है।

यही अंधराष्ट्रवाद का असली चेहरा है जिसका बड़ा मकसद युद्धोन्माद पैदा कर अति उत्पादन के संकट से जूझ रहे पूँजीपतियों को राहत पहुंचाने के लिए उच्च मुनाफे देने वाले अस्त्र-शस्त्र की भारी खरीद करना है, युद्धोन्माद से होने वाला राजनीतिक फायदा और जनवादी अधिकारों-आंदोलनों के दमन का माहौल तैयार करना तो साथ में है ही।

वहीं आम सैनिक तो अधिकांश गरीब-मध्य किसान तबके से आते हैं, उनमें व्याप्त भयंकर बेरोजगारी-कंगाली के माहौल के कारण जो नौकरी मिले, जिस कीमत पर मिले, जितने वेतन वाली मिले, तोप-बंदूक का चारा बनने वाली ही क्यों न हो, अपने मेहनतकश वर्ग बंधुओं पर गोली-लाठी चलाने वाली ही क्यों न हो, उसके लिए ही एक की जगह पर हजारों हाथ फैलाये मौजूद हैं। पर इससे मांग-पूर्ति के नियम से उनका खुद का बाजार मूल्य गिर गया है, अब उन्हें भी विशेष सुविधाएं देने की कोई वास्तविक आवश्यकता न रही - घटिया खाना है तो चुपचाप खाओ, वर्दी चाहिए तो खुद खरीद लाओ।

इसका दूसरा पक्ष लाखों रोजगार वाले ओर्डनेंस कारखानों को घाटे में पहुंचाकर तालाबंदी, निजी मुनाफे के लिए कौड़ियों के दाम बिक्री, छंटनी, बेरोजगारी तो है ही।

खबर (दार) झरोखा

सेंधमार बैंकर के हवाले ख़ज़ाने की चाभी

गिरीश मालवीय

सरकार ने आईडीबीआई बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ महेश कुमार जैन को भारतीय रिजर्व बैंक का डेप्युटी गवर्नर नियुक्त कर दिया। कुछ दिनों पहले एक खबर आयी थी कि रिजर्व बैंक ने निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए उसने आईडीबीआई बैंक पर तीन करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

केंद्रीय बैंक ने अपने बयान में कहा था कि, "आरबीआई ने नौ अप्रैल, 2018 के अपने एक आदेश के जरिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड पर आय की पहचान और परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंडों को लेकर जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर तीन करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।"

जुर्माना लगाए जाने के वक्त जैन साहब ही आईडीबीआई बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ थे इनके कार्यकाल में बैंक ने इतनी प्रगति की है कि कल बढ़ते एनपीए के बोझ से जिन चार बैंको का मर्जर किये जाने की बात की जा रही है उसमें से आईडीबीआई प्रमुख बैंक है।

आईडीबीआई बैंक ने 2017-18 की जनवरी-मार्च तिमाही के नतीजे जारी किए। इस आखिरी तिमाही में बैंक को 5,662.76 करोड़ का नुकसान हुआ है। एनपीए की ऊंची प्रोविजनिंग घाटे की बड़ी वजह रही मार्च 2017 में आईडीबीआई बैंक का ग्रॉस एनपीए 21.25% था जो बढ़कर 27.95% हो गया है। वहीं नेट एनपीए 13.21% से बढ़कर 16.69% हुआ हैं यह सब जैन साहब के कार्यकाल के ही आँकड़े है, आईडीबीआई इस चोथी तिमाही में पीएनबी ओर एसबीआई के बाद घाटा दर्शाने वाला तीसरा बड़ा बैंक है।

2017 में आईडीबीआई के ष्टश्वह्व बनने से पहले महेश कुमार जैन साहब इंडियन बैंक के मुख्य कार्यकारी का पद संभाल रहे थे। कुछ वक्त पहले इंडियन बैंक और अन्य बैंको पर बिहार के सृजन घोटाले में शामिल होने के आरोप लगे थे 2013में सूरत की विंसेट डायमंड भी इंडियन बैंक का 4500 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाने में विफल रही किसने इस कर्ज को मंजूरी दी थी पता नही है।

कुछ दिनों पहले सीबीआई ने एयरसेलके पूर्व प्रवर्तक सी शिवशंकरन की दो कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है इसमें भी इंडियन बैंक का नाम शामिल है।

वैसे तुर्रा यह है कि जैन साहब का नाम 37 अभ्यर्थियों में से फाइनल किया गया हैं।

ग्रेनो में जमीन के लिए लाला रामदेव ने दी योगी सरकार को धमकी

ठग गुरु हर राज्य में अपने हिसाब से हड़पना चाहता है प्लॉट

गिरीश मालवीय

लाला रामदेव देश के सबसे बढ़ा जमीन हड़पने वाले बाबा हैं। पहले के जमाने में बाबा छोटे बच्चों को झोले में छिपाकर उठा ले जाते है अब मॉडर्न बाबा बड़े ठसके के साथ देश के हर छोटे बड़े राज्य में जाता है और वहाँ के मुख्यमंत्री और प्रशासनिक अमले को पटा कर ज्यादा से ज्यादा जमीन कबजाता है और उद्योग लगाने के नाम पर दस तरह के धतकरम करता है।

लाला रामदेव धमकी दे रहे हैं कि नोएडा में बनने वाले मेगा फूड पार्क को उठा कर दूसरी जगह ले जाएंगे लेकिन सोचने की बात तो ये है कि लेकर जाएगे कहां?, उत्तराखंड के हरिद्वार मे तो फूड पार्क चल ही रहा है। मध्य प्रदेश , छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, असम, और राजस्थान जैसे राज्यों में तो उन्होंने पहले ही फूड पार्क की नींव रखी है, वही अभी पूरे नही हो रहे है और सभी जगह यही सवाल उठेंगे तो आखिर जाएगे कहां ?

दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह हैं कि जिस मेगा फूड पार्क की बात की जा रही है वह तो मात्र 50 एकड़ में खड़ा किया जाने वाला है तो ये बाकी 405 फूड किसलिए इन्हें सस्ती दर पर चाहिए।

ये लाला रामदेव जमीनों के कितना भूखे हैं, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा लीजिये कि आज से दो साल पहले जब मध्य प्रदेश सरकार ने इसे मेगा फूड पार्क के लिए पीतमपुर में 45 एकड़ जमीन देने की घोषणा की तो रामदेव ने इन्वेस्टर समिट के मंच पर बैठे उद्योगपतियों को शर्मसार करते हुए मध्यप्रदेश सरकार को ताना मारा कि, 45 एकड़ जमीन पर तो वह कबड्डी खेलते हैं।

हर जगह इन्हें आवश्यकता से अधिक जमीन चाहिए और इस जमीन का टाइटिल भी अपने नाम पर रजिस्टर्ड चाहिए और साथ ही मेगा फूड पार्क की स्थापना के लिए दी जाने वाली केंद्र सरकार 150 करोड़ रुपये सब्सिडी भी ये हड़प जाएंगे।

उत्तर प्रदेश में भी यही बात हुई है ...सरकारी स्कीम में मनमाने परिवर्तन करिए ओर अधिक से अधिक जमीन पर कब्जा कीजिये ये इनकी मोडस ऑपरेंडी है।

जो जमीन नोएडा में लाल रामदेव की कंपनी को दी गई, वह पहले कई किसानों को 30 साल के पट्टे पर दी गई थी। बिना इजाजत अखिलेश सरकार में लाला रामदेव ने वहाँ 6000 पेड़ कटवा दिए। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस भी चल रहा है लेकिन यहाँ कोई पर्यावरण प्रेमी इस बात का संज्ञान लेना नही चाहता।

अब आते हैं नवीनतम घटनाक्रम पर ...बालकृष्ण ने ट्वीट किया कि ग्रेटर नोएडा में केन्द्रीय सरकार से स्वीकृत मेगा फूड पार्क को निरस्त करने की सूचना मिली।

श्रीराम व कृष्ण की पवित्र भूमि के किसानों के जीवन में समृद्धि लाने का संकल्प प्रांतीय सरकार की उदासीनता के चलते अधूरा ही रह गया। पतंजलि ने प्रोजेक्ट को अन्यत्र शिफ्ट करने का निर्णय लिया।

इस ट्वीट के जवाब में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बालकृष्ण से देर रात टेलीफोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने संबंधित नीति के तहत उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। सुबह होते-होते यूपी सरकार ने घुटने टेक दिए।

अब आप इस खेल को समझिये जो बालकृष्ण खेल रहे हैं सीधी बात तो यह है कि वह चाहते हैं कि योगी सरकार 50 एकड़ की भूमि के टाइटल पतंजलि के नाम करने के बहाने अधिक से अधिक भूमि का टाइटिल ही पतंजलि के नाम कर दे...पतंजलि ग्रुप के प्रवक्ता एस के तिजारावाला बता रहे है कि 'नोएडा में बनने वाले पतंजलि फूड पार्क की जमीन के टाइटल सूट के लिए केंद्र सरकार की ओर से दो बार नोटिस भेजा गया था। लेकिन योगी सरकार की ओर से पतंजलि को टाइटल सूट नहीं सौंपा गया।

अब दबाव में आकर योगी सरकार केबिनेट के बैठक में इस जमीन का टाइटिल सौपने को राजी हो गयी है लेकिन सब मिला जुला खेल है।

ऐसा ही एक मामला मध्यप्रदेश के मन्दसौर का है। जहाँ प्रस्तावित फूड पार्क को बनाने वाली कम्पनी ऐसा ही चाह रही थी जैसे लाला रामदेव चाह रहे हैं। लेकिन स्थानीय कलेक्टर ने जमीन का नामांतरण कंपनी के नाम पर करने से इंकार कर दिया और इस मामले को लेकर वह हाईकोर्ट भी चले गए। मामला कोर्ट में होने से जब तक इस पर फैसला नहीं होता, फूड पार्क का काम आगे नहीं बढ़ेगा ...लेकिन यह मामला पतंजलि से संबंधित नही था। इसलिए यह सम्भव हो पाया। यहाँ तो केंद्र और राज्य सरकारें और मीडिया तीनो ही गोदी में बैठे हुए हैं इतनी बात करने की किसी की हिम्मत ही नहीं है।

कुल मिलाकर सत्तासीन लोगों से सांठगाँठ कर देश भर में मेगा फूड पार्क के नाम दोगुनी चौगुनी जमीन को बेहद मामूली दर पर खरीद कर ही पतंजलि इतनी जल्दी सफलता की सीढ़ी चढ़ पाया है। इस बात में किसी को शक नहीं होना चाहिए।

सावरकर, गोलवालकर, श्यामा प्रसाद क्यों प्रधानमंत्री नही बने ....

1946 के चुनाव 1585 सीटो पर हुये थे।।कांग्रेस ने 923 सीटे जीती थी....कुल हिन्दू वोट का 91ब कांग्रेस को मिला था।...और आप? तो सुनिये = आपके पास तो उम्मीदवार भी नही थे।। हिन्दू महासभा के केवल 18 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे और सब हार गये थे।।आपका सूपड़ा साफ हो गया था।। हिंदुवो ने आपलोगों के मुह पर करारा थप्पड़ मारा था।। औकात क्या है ये सवाल करने की? नेहरू घोषित चेहरा थे कांग्रेस के उन चुनावो में।।चुनाव कांग्रेस ने जीता था और कांग्रेस ने चुनाव के पहले ही बोल दिया था कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री।।

आगे सर झुका कर जवाब सुनते जाइये।।।

एक झूठी कहानी के इर्द गिर्द पूरा ताना बाना बुना गया है।। 1946 में बापू ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) से वोट लिये थे प्रधानमंत्री पद के लिये।। 15 वोट पटेल के पक्ष में थे और बस एक वोट नेहरू के पक्ष में।। फिर भी बापू ने नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया।। ये सबसे बड़ा झूठ, असत्य और नीचता है।। ऐसा कुछ भी नही हुवा था।।

भारत मे किसी भी प्रधानमंत्री का चयन भारत के संविधान और विजयी दल के संविधान के आधार पर होता है।। उसकी एक मुकम्मल प्रकिया है।।

1 PCC को प्रधानमंत्री चुनने का कोई अधिकार नही होता है कांग्रेस के संविधान में।। क्या अटल और मोदी , बीजेपी के प्रदेश कमेटियों द्वारा चुने गये थे? जवाब दीजिये?

2 किसी भी दल की प्रदेश कमेटी को प्रधानमंत्री तो छोड़िये, मुख्यमंत्री तक चुनने तक का अधिकार नही होता।। या तो पहले से चेहरा घोषित किया जाता है या चुनाव के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड चुनता है , जैसे खट्टर, फडणवीस, मनोहर दास वगैरह।।जवाब दीजिये?

3 कांग्रेस वर्किंग कमेटी और कांग्रेस अध्यक्ष प्रधानमंत्री चुनते है।।बीजेपी में भी पार्लियामेंट्री बोर्ड ही प्रधानमंत्री का चुनाव करता है।। जैसे कांग्रेस ने डॉ मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री चुना था, सोनियाजी के सर्वसम्मत चुने जाने के बावजूद।।

4 एक झूठ और बोला जाता है कि PCC, कांग्रेस अध्यक्ष को चुनती थी और कांग्रेस अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री बनता था।।ये कहा लिखा है कांग्रेस के संविधान में? कांग्रेस का संविधान तो इंटरनेट पर उपलब्ध है।।दिखा दीजिये।।

5 PCC कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नही चुनती। AICC के प्रतिनिधि ही कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव करते है।।

6 और अगर इस संघी झूठ को सही मान भी लिया जाये तो फिर आचार्य कृपलानी को प्रधानमंत्री बनना चाहिये था।।क्योंकि स्वाधीनता के वक्त नेहरू या पटेल नही, आचार्य कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे।।कोई जवाब है?

1936-37 के प्रोविंशियल चुनाव से ले कर 1946 या उसके बाद तक जो भी चुनाव कांग्रेस ने 1964 तक लड़े, सारे चुनावो में नेहरू ही कांग्रेस का घोषित चेहरा थे।।और कोई नही था।।

सवाल अगर योग्यता का है तो किस योग्यता के आधार पर बीजेपी ने मोदीजी को प्रधानमंत्री और अमित शाह जी को अध्यक्ष चुना है? क्या उनसे ज्यादा योग्य कोई नही था? आजभी बीजेपी से ही लोग बोलते है कि आडवाणी , मोदी से बेहतर प्रधानमंत्री होते।।योग्यता तो एक आपेक्षिक शब्द है।।

योग्यता की तो बात ही मत कीजिये।। बापू, नेहरू और पटेल तीनो की शैक्षणिक योग्यता मालूम है? इन तीनो का राजनैतिक कद दुनिया के किसी भी नेता से बड़ा है।। खुद की योग्यता बताइये।। हमारे महापुरुषों की योग्यता पर बोलने का हक क्या है आपलोगो को? पटेल कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी थे और नेहरू कांग्रेस का चेहरा, केवल भारत मे ही नही , पूरे विश्व मे।।।

हर जमाने मे राजनैतिक समीकरण होते है।। जैसे अटल- आडवाणी, इंदिरामा - प्रणव मुखर्जी वगैरह।। गांधी - नेहरू - पटेल-सुभाष की चौकड़ी विश्व का सर्वश्रेष्ठ राजनैतिक समीकरण माना जाता है जिसने भारत को आज इस मुकाम पर पहुंचाया।।

एक और बात = आज़ादी के वक्त दो लोगों की सेहत को गोपनीय रखा गया।।एक जिन्नाह और दूसरे पटेल।। अगर इन दोनों की सेहत का राज खुल जाता तो सबकुछ उल्टा पुलटा हो जाता।।दोनो पर अपने अपने देश को स्थापित करने की जिम्मेदारियां थी।।जिन्नाह और पटेल दोनो की तबियत का अचानक खराब हो जाना और दोनो का इस दुनिया से चले जाना, इस बात को ही साबित करता है।। **1947 में भारत की संसद नही संविधानिक सभा थी।। वो एक अंतरिम व्यवस्था थी जिसे आज़ाद भारत का संविधान से लेकर सेना तक बनाना था।। भारत के पहले चुनाव तो 1951-52 में हुये थे।।और सरदार पटेल का देहांत तो 1950 में हो चुका था। तो पटेल का पहला प्रधानमंत्री बनने का सवाल आता कहा से है?** नेहरू का चुनाव सर्वसम्मत रूप से हुवा था जो कि स्वाभाविक था और कांग्रेस के अंदरूनी मामले में किसी भी ब्रिटिश मुखबिर, दलाल को बोलने का कोई हक नही।

- नीरज रस्तोगी